बड़े अस्पतालों में जांच, दवा और उपचार के लिए होगा प्रभावी प्रबंधन

दवा आपूर्ति एवं भण्डारण तंत्र को मजबूत करेगी राज्य सरकार

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध सभी बड़े अस्पतालों में जांच, दवा, उपचार एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। अस्पतालों में जन औषधि केंद्र एवं अमृत फार्मेसी प्राथमिकता के साथ खोली जाएंगी। दवाओं के भण्डारण तंत्र को मजबूत किया जाएगा। साथ ही, रोगियों को कतारों से मुक्ति दिलाने एवं सुगमता से इलाज उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अन्य अस्पताल जहां रोगी भार अत्यधिक रहता है, वहां भी ईवनिंग ओपीडी शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने गुरूवार को चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राय: देखने में आता है कि कई बड़े अस्पतालों में रोगियों का भार अधिक होने के कारण उन्हें इलाज लेने में परेशानी आती है। ओपीडी में लंबे समय तक रोगियों को इंतजार करना पड़ता है। इसे देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट के लिए ईवनिंग ओपीडी की व्यवस्था के प्रयास किए जाएं। अस्पतालों में आवश्यकतानुसार दवा वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने नए मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त फैकल्टी एवं संसाधन उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए।

राठौड़ ने कहा कि गर्मी के मौसम में अस्पतालों में आग की घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, इसे ध्यान में रखते हुए फायर सेफ्टी के सभी मानकों को जांचा जाए। सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी आडिट आवश्यक रूप से हो। साथ ही, सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाए। उन्होंने सभी अस्पतालों में गर्मी को देखते हुए रोगियों एवं परिजनों के लिए छाया एवं पानी का समुचित प्रबंध करने के भी निर्देश दिए।

दवा उपलब्धता की नियमित समीक्षा कराएं

प्रमुख शासन सचिव ने मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के तहत आपूर्ति की जाने वाली दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि रोगियों को आवश्यक दवा सूची में निर्धारित सभी दवाएं आवश्यक रूप से उपलब्ध हों। उन्हें दवाओं के लिए भटकना नहीं पड़े। उन्होंने राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री पुखराज सेन को निर्देश दिए कि प्रदेशभर में दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा करवाएं, जहां भी दवाओं की कमी है, वहां तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही, जिन दवाओं के रेट कॉन्ट्रेक्ट होना शेष है, उनकी दर संविदा जल्द की जाए। उन्होंने दर संविदा होने तक नियमानुसार स्थानीय स्तर पर दवाओं की खरीद कर रोगियों को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। श्रीमती राठौड़ ने कहा कि हीटवेव एवं मौसमी बीमारियों से संबंधित दवाएं हर अस्पताल एवं आवश्यक रूप से उपलब्ध हो।

दवा भण्डारण में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

राठौड़ ने कहा कि हर अस्पताल एवं औषधि भण्डार गृहों के प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि दवाओं का भण्डारण प्रोटोकॉल के अनुसार हों। भण्डारण में किसी भी तरह की लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि औषधि भण्डार गृहों एवं दवा वितरण केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी अस्पताल में अनावश्यक रूप से दवाएं रखी हों तो उन्हें जहां आवश्यकता है, वहां भिजवाया जाए, ताकि वे अवधिपार नहीं हों। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि सभी अस्पताल सही आकलन कर दवाओं की व्यावहारिक मांग पोर्टल पर भेजें, ताकि दवाओं की कमी या अधिकता की स्थिति नहीं हो।

अधिशेष व खराब उपकरणों की रिपोर्ट मांगी

प्रमुख शासन सचिव ने अस्पतालों में उपलब्ध उपकरणों की क्रियाशीलता एवं उपयोग को लेकर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसी अस्पताल में उपकरण अधिशेष मात्रा में है तो उसकी जानकारी तत्काल भिजवाएं, ताकि उनका उपयोग जहां आवश्यकता है, वहां हो सके। उन्होंने खराब उपकरणों को तत्काल ठीक करवाने के भी निर्देश दिए।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने गुरूवार को चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक ली।

- प्रमुख शासन सचिव ने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं अधीक्षकों को निर्देश दिए
- हीटवेव प्रबंधन, दवा उपलब्धता, बजट घोषणा, फायर सेफ्टी एवं अन्य व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की

समय पर पूरे हों प्रोजेक्ट, गुणवत्ता का रखें ध्यान

राठौड़ ने कहा कि हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जो बजट घोषणाएं की गई हैं, उनका काम टाइमलाइन में पूरा किया जाए। साथ ही, जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं उनका काम गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। नियमित मॉनिटरिंग करते हुए उन्हें समय पर पूरा किया जाए। कोई प्रोजेक्ट किसी तकनीकी या अन्य कारण से अधूरा है तो राज्य स्तर पर अवगत कराएं। पीडब्ल्यूडी, आरएसआरडीसी सहित अन्य निर्माण एजेंसियां के साथ बेहतर समन्वय किया जाए। उन्होंने अन्य बजट घोषणाओं को भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। आरएमएससीएल के प्रबंध निदेशक पुखराज सेन ने कहा कि दवाओं की समुचित उपलब्धता के लिए समयबद्ध रूप से दर संविदा किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दवाओं के प्रोटोकॉल के अनुसार भण्डारण के लिए एयर कंडीशनर सहित अन्य संसाधनों की कहीं भी आवश्यकता हो तो अवगत कराएं, आरएमएससीएल के माध्यम से इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल, आरएमएससीएल के विशेषाधिकारी जय सिंह, सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य, अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जयपुर स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री ने किया स्वागत

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जयपुर पहुंचने पर उनकी अगवानी की तथा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, सांसद मदन राठौड़ सहित अधिकारी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्री ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सप्त शक्ति कमान में आयोजित संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जयपुर आए हैं।

गैर पारंपरिक स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन में देश का ''एनर्जी इंजन'' बनकर उभरा राजस्थान

विगत दो वित्तीय वर्षों में 12 हजार करोड़ यूनिट से अधिक उत्पादन कर मजबूत कदम बढ़ाए

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान सिरमौर बन गया है। इतना ही नहीं राजस्थान गैर पारंपरिक स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश का 'एनर्जी इंजन' बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में विगत दो वर्षों में राजस्थान ने 12 हजार 647 करोड से अधिक यूनिट बिजली उत्पादन कर ऊर्जा आत्मनिर्भता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए हैं।

राजस्थान का गैर-पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन 2024-25 में 5735 करोड़ से अधिक यूनिट तक पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही राजस्थान 6912 से अधिक यूनिट का आंकड़ा पार कर चुका है। गैर-पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन में साल दर साल हो रही बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि राजस्थान वैकल्पिक स्त्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

सौर ऊर्जा क्षमता राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि राजस्थान ने 'सोलर कैपिटल ऑफ इंडिया' के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। राज्य में सालभर प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है, जिससे यहां सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श परिस्थितियां बनती हैं। 2024-25 में राजस्थान का सौर ऊर्जा उत्पादन 4910 करोड़ यूनिट से अधिक हो गया। वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़कर 5992 करोड़ यूनिट से अधिक हुआ।

सौर ऊर्जा के साथ-साथ राजस्थान ने पवन, बायोमास एवं लघु हाइड्रो ऊर्जा जैसे गैर-पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जैसे राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। विगत दो वर्षों में पवन ऊर्जा से 1428 करोड़ से अधिक यूनिट उत्पादन किया। बायो मास में 117 करोड़ से अधिक यूनिट, लघु हाइड्रो से 1 करोड़ से अधिक यूनिट, लार्ज हाइड्रो से भी 197 करोड़ यूनिट से अधिक ऊर्जा का उत्पादन किया गया है। यह प्रमाण है कि राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा स्त्रोतों के विविधीकरण पर प्रमुखता से ध्यान दिया जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ली पर्यटन विभाग की बैठक

पर्यटन विकास कार्यों को गति प्रदान करने के दिए निर्देश

जयपुर (कासं)। उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता तथा शासन सचिव शुचि त्यागी एवं पर्यटन आयुक्त रुक्मिणी रियाड़ की उपस्थिति में गुरुवार को सचिवालय में विभागीय समीक्षा बैठक हुई। दिया कुमारी ने राज्य में पर्यटन विकास के लिए ढांचागत सुविधाओं का विकास शीघ्रता से किए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं सहज सुलभ हो। उन्होंने शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण और जीर्णोद्धार कार्य को गति प्रदान करने के साथ ही निर्देश दिए कि इस क्षेत्र में पर्यटन विकास की मूलभूत सुविधाओं का विकास प्राथमिकता से किया जाए।

- पर्यटकों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं सहज सुलभ हो : दिया कुमारी

उन्होंने इसके साथ ही बावड़ियों संरक्षण कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर राज्य में चिन्हित बावड़ियों के जीर्णोद्धार कार्यों को विशेषज्ञ कंसलटेंट्स के पर्यवेक्षण में उनकी मूल वास्तुशैली के अनुरूप कार्य कराने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में सेंटर सम्बन्ध में चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सेंटर, विद्याधर नगर के लिए जेडीए द्वारा पर्यटन विभाग के नाम पट्टा जारी के पश्चात इस हेतु जेडीए के सहयोग से आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दिया कुमारी ने पुष्कर विकास परियोजना की भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में अभी तक की प्रगति से अवगत कराया। उपमुख्यमंत्री ने पर्यटन ऐप की समीक्षा करते हुए इसे शीघ्रता से विकसित किये जाने के निर्देश दिए। दिया कुमारी ने आरटीडीसी की परिसम्पत्तियों की स्थिति पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। अधिकारियों ने अवगत कराया कि विभागीय परामर्श दाता फर्म द्वारा एक स्टडी रिपोर्ट का प्रारूप उपलब्ध करवाया गया है। जयपुर के चारदीवारी शहर में पर्यटन केंद्र पर टीएफसी के लिए नवीन निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उपमुख्यमंत्री ने आमेर लाइट एंड साउंड शो हेतु आवश्यक प्रक्रिया को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने आमेर-नाहरगढ़ एवं आसपास का क्षेत्र के विकास प्रोजेक्ट को भी गति प्रदान करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार जल महल का विकास कार्य को भी गति प्रदान करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार आमेर मास्टर प्लान की डीपीआर पर चर्चा कर उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। उक्त परियोजना की लागत 50 करोड़ रुपये है, जिसमें से 11 करोड़ रुपये के कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) द्वारा तैयार की जाएगी। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की और शेखावाटी क्षेत्र में ऐतिहासिक हवेलियों का जीर्णोद्धार को प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस मौके पर शासन सचिव शुचि त्यागी एवं पर्यटन आयुक्त रुक्मिणी रियाड़ समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

आदिवासी जिलों में बच्चों की मौत पर जवाबदेही तय करें सीएम : जूली

जयपुर । नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रतापगढ़ दौरे को लेकर तीखे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में 15-16 मासूम बच्चों की अज्ञात बीमारी और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में अकाल मृत्यु हो गई, मुख्यमंत्री वहां जाकर भी उन शोक संतप्त परिवारों की सुध नहीं लेते। जूली ने पूछा, "मुख्यमंत्री जी, क्या आप उन जिम्मेदार सरकारी लोगों की जवाबदेही तय करेंगे, जिनकी लापरवाही से इन परिवारों ने अपने नौनिहालों को खो दिया? यदि आप उनके आंसू नहीं पोंछ सकते, तो आपका यह दौरा महज एक सैर-सपाटा और फोटो अपॉर्चुनिटी बनकर रह गया है।"

उन्होंने कहा कि "आदिवासी जिलों में अज्ञात बीमारी से बच्चों की मौत, कोटा में प्रसूता की मौत, श्रीगंगानगर में दलित इंजीनियर की पिटाई तथा अलवर के दलित नाबालिग बच्चे से पुलिस बर्बरता के मुद्दों पर मुख्यमंत्री की चुप्पी चिंताजनक है।" उन्होंने याद दिलाया कि जब झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से मासूम बच्चों की जान गई, तब भी मुख्यमंत्री ने वहां जाने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि घटनाएं और दुर्घटनाएं दुखद होती हैं, लेकिन एक जिम्मेदार मुखिया का दायित्व होता है कि वह पीड़ित के साथ खड़ा हो। दुर्भाग्य से, राजस्थान में आज ऐसी सरकार है जिसे जनता के दर्द से ज्यादा अपनी छवि की चिंता है।

अस्पतालों की होगी अग्नि सुरक्षा जांच

सीएमएचओ की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह जयपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में स्थापित अस्पतालों में पर्याप्त फायर फायटिंग सिस्टम के संबंध में रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने कहा कि यदि किसी भी अस्पताल में उचित अग्निशमन प्रणाली नहीं पाई जाती है तो संबंधित सीएमएचओ की ओर से तय टाइम लाइन के साथ उसे नोटिस जारी किए जाए। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बीस बेड से अधिक क्षमता वाले हर अस्पताल व क्लिनिक की ओर से पर्याप्त सुरक्षा उपायों को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों की पालना की जा रही है। अदालत ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक अस्पताल में नियमित रूप से फायर ड्रिल आयोजित की जाए और फायर सेफ्टी प्रणाली का ज्ञान रखने वाले कम से कम दो विशेषज्ञों को प्रत्येक सरकारी अस्पताल में तैनात किया जाए।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि निजी अस्पतालों को भी इसी तरह के कदम उठाने होंगे और अपनी रिपोर्ट संबंधित सीएमएचओ को सौंपनी होगी। अदालत ने इस संबंध में जुलाई माह के दूसरे सप्ताह में सुनवाई तय करते हुए रिपोर्ट पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि नवंबर, 2024 में झांसी के एक मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशु वार्ड में आग लगने से दस नवजातों की मौत हो गई थी। इस पर अदालत ने प्रदेश के सरकारी अस्पताल के पास फायर एनओसी नहीं होने के मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए अधिवक्ता राजेश मुथा को न्यायमित्र नियुक्त किया था।

आदेश की पालना नहीं करने पर अफसरों को अवमानना नोटिस

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी सफाई कर्मचारियों के अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं करने पर प्रमुख स्थानीय निकाय सचिव रवि जैन, निदेशक जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर और टोडारायसिंह के अधिशासी अधिकारी पवन कुमार को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश शंकर लाल माली व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता स्थानीय नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। जिन्हें नगर पालिका ने मई, 2023 को निलंबित कर दिया था। वहीं नगर पालिका की ओर से अप्रैल, 2024 से निर्वाह भत्ते का भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गत 5 मार्च को याचिकाओं का निस्तारण करते हुए नगर पालिका को याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का तीस दिन में निस्तारण करने को कहा था।

''ग्राम'' के तहत आज हैदराबाद में होगी इनवेस्टर मीट

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे फार्मा कंपनियों, निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद

जयपुर। राजस्थान को कृषि नवाचार, एग्रीटेक निवेश और तकनीक आधारित कृषि विकास का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में कृषि विभाग, राजस्थान द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) तथा राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026' के तहत 8 मई शुक्रवार को हैदराबाद में एक महत्वपूर्ण इनवेस्टर मीट आयोजित की जा रही हैं, जिसमें कृषि, एग्रीटेक, आईटी, बीज प्रौद्योगिकी, संरक्षित खेती और कृषि अनुसंधान से जुड़े प्रमुख उद्योग प्रतिनिधि, निवेशक और विशेषज्ञ भाग लेंगे। रोडशो के दौरान स्कोप ऑफ आईटी इंटरवेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन एग्रीकल्चर विषय पर विशेष पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी।

पैनल चर्चा में आईटीसी, कोरोमंडल, नुजिवीडु सीड्स, खेयती, आईसीआरआईसैट तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयलसीड्स रिसर्च (आईआईओआर) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों और कंपनियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। चर्चा के दौरान राजस्थान में एग्रीटेक विस्तार, तकनीकी नवाचार, इंटर-स्टेट सहयोग तथा कृषि निवेश के नए अवसरों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे तथा उनके साथ राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री निवेशकों, उद्योगपतियों और राजस्थान फाउंडेशन के सदस्यों के साथ विशेष संवाद भी करेंगे, जिसमें राजस्थान में कृषि आधारित निवेश, एग्रीटेक स्टार्टअप्स, प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन और तकनीकी साझेदारी के अवसरों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा एग्रीटेक कंपनियों के साथ साथ फार्मा कंपनियों से भी वन ऑन वन मीटिंग की जाएंगी।

सहकारी समितियों में गबन-घोटालों के मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे : मंत्री गौत्तम दक

रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाने वाली समितियों के विरूद्ध दर्ज करवाएं एफआईआर : सहकारिता मंत्री

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारी समितियों में गबन-घोटालों के मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसे प्रकरण सामने आने पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों की ऑडिट एवं आमसभा समयबद्ध रूप से सम्पन्न होने से गबन-घोटालों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। दक गुरूवार को अपेक्स बैंक सभागार में नाबार्ड एवं शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा 'सहकारिता में सहकार' अभियान के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी समितियों की ऑडिट अनिवार्य रूप से जून माह से पूर्व एवं आमसभा सितम्बर माह से पूर्व सम्पन्न करवाई जाए। आमसभा में सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि आवश्यक रूप से उपस्थित रहे तथा आमसभा की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करवाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आमसभा के आयोजन से पूर्व इसकी सूचना समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से आमजन को दी जाए। साथ ही, आमसभा में समिति की सम्पत्ति एवं जमाओं की जानकारी सार्वजनिक की जाए।

सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिए कि जो समितियां ऑडिट के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवा रही हैं, उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाए। गबन-घोटालों के सभी मामलों में वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनियमितता करने वाले व्यक्ति व उसके परिवार की सम्पत्ति को अटैच करवाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्रदान किये गए ऋणों की शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए। योजना के अंतर्गत नये आवेदकों को ऋण उपलब्ध करवाये जाएं तथा ऋण वितरण में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने ऋण प्राप्त करने वाले परिवारों से फीडबैक लेकर ऋण वितरण में कमीशन लेने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कार्रवाई के भी निर्देश दिए। दक ने सहकारी बैंकों के विस्तार की आवश्यकता व्यक्त करते हुए नई शाखाएं खोलने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने नये खाते खोलने, जमाएं बढ़ाने तथा अकृषि ऋण वितरण पर फोकस करने के भी निर्देश प्रदान किए। सहकारिता मंत्री ने निर्देशित किया कि पैक्स कम्प्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत शत प्रतिशत डायनामिक डे-एंड करवाया जाए तथा आधार इनेबल्ड बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को पैक्स स्तर तक लागू किया जाए।

सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा ने म्हारो खातो, म्हारो बैंक विषय पर चर्चा करते हुए अधिक से अधिक सक्रिय दुग्ध सहकारी समितियों के खाते सहकारी बैंकों में खोले जाने पर विशेष जोर दिया। राजफेड के प्रबंध निदेशक सौरभ स्वामी ने कहा कि दुग्ध सहकारी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा सहकारी बैंकों में खाता खोलने के साथ-साथ लेनदेन भी सहकारी बैंकों से किया जाना अति आवश्यक है, इसके लिए जिला स्तर पर कार्यवाही की जाए।

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. आर. रवि बाबू ने कहा कि गुजरात के बनासकांठा की तरह राज्य की सहकारी संस्थाओं को भी आपस में सामंजस्य व समन्वय स्थापित कर प्रगति करनी चाहिए। कार्यशाला में नाबार्ड के शीर्ष सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक रणजीत सिंह चूंडावत, सहकार से समृद्धि के कंसल्टेंट आर.एस. जोधा एवं चूरू सीसीबी के प्रबंध निदेशक मदनलाल द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। कार्यशाला में नाबार्ड, सहकारिता विभाग, डेयरी, मत्स्य पालन एवं अपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारी तथा सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक उपस्थित रहे।

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने गुरूवार को नाबार्ड एवं शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा 'सहकारिता में सहकार' अभियान के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित किया।

- गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में नये आवेदकों को उपलब्ध करवाएं ऋण : दक